नईदुनिया

व्हाइट हाउस में लश्कर के संदिग्ध आतंकी की एंट्री, बनाया गया बोर्ड सदस्य

वाशिंगटन

अमेरिका के व्हाइट हाउस में एक ऐसे व्यक्ति की तैनाती हो गई है, जो कि लश्कर का संदिग्ध आतंकवादी रहा है। व्हाइट हाउस की एडवाइजरी बोर्ड आफ ले लीडर्स में इस संदिग्ध इस्लामिक आतंकवादी को शामिल किया गया है।

इन नियुक्तियों ने जहां भारत के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय जगत में चिंता पैदा कर दी है, वहीं दक्षिणपंथी कार्यकर्ता लारा लूमर भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ट ट्रम्प के प्रशासन से खासे खफा हैं। दरअसल अमेरिका प्रशासन ने बीते व्हाइट हाउस की एडवाइजरी बोर्ड आफ ले लीडर्स का गठन किया। इसमें इस्माइल रायर और मुस्लिम स्कालर शेख हमजा यूसूफ को भी नामित किया गया। कथित तौर पर इस्माइल रायर के इस्लामी जिहादियों से संबंध रहे हैं। दावा है कि इस्माइल रायर पहले रेंडेल रायर के नाम से जाना जाता था। कथित तौर पर इसके संबंध पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से रहे हैं। आरोप है कि रायर ने वर्ष 2000 में पाकिस्तान में हुए लश्कर के ट्रेनिंग सेंटर में भाग लिया था और कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में भी शामिल रहा है। दूसरे नामित सदस्य शेख हमजा यूसूफ मुस्लिम स्कालर होने के साथ ही जायतूना कालेज के सह संस्थापक हैं। उन पर भी कथित तौर पर इस्लामिक कट्टरपंथियों से संबंध रखने के आरोप हैं। दक्षिणपंथी कार्यकर्ता लारा लूमर ने इस्माइल रायर की तैनाती पर खासी नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने इसे अमेरिकी प्रशासन का एक आत्मघाती कदम बताते हु कहा इस्माइल रायर लश्कर ए तैयबा के आतंकी कैंप में ट्रेनिंग ले चुका है। उसने कश्मीर में भारतीय ठिकानों पर फायरिंग जैसी गतिविधियों में भी हिस्सा लिया। अमेरिका की अदालत ने भी 2004 में रायर को आतंकवादी गतिविधियों के लिए दोषी पाते हुए 20 साल की सजा सुनाई थी। इसमें उसने 13 साल जेल में बिताए हैं। रायर ने वर्ष 2003 में मिडिल ईस्ट फोरम के साथ एक इंटरव्यू में कबूल किया था कि मुझे लश्कर के लोग पसंद आए। यह एक चरमपंथी समूह नहीं हैं।

न्यूज ब्रीफ

नए पोप लिओ का होगा शपथ ग्रहण

वेटिकन सिटी। नए पोप लिओ-14 का वेटिकन सिटी के सेंट पीटर स्कावयर पर शपथ ग्रहण समारोह होगा। यह समारोह जो कि पूरे दो घंटे तक चलेगा। इस शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए दुनिया भर के तमाम नेता वेटिकन सिटी पहुंच चुके हैं। रोमन कैथोलिक चर्च के पूर्व पोप फ्रांसिस का पिछले महीने 21 अप्रैल को 88 साल की आयु में निधन हो गया था। उसके बाद आठ मई को कार्डिनल ने वोटिंग करके नए पोप के तोर पर लिओ का नाम तय किया था। नए पोप लिओ का असली नाम राबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट है। कैथोलिक परम्परा के मुताबिक शपथ ग्रहण के बाद नए पोप को एक धार्मिक वस्त्र और एक अंगूठी दी जाएगी। ये उपहार नए पोप के पदभार ग्रहण करने का प्रतीक होते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पोप के शपथ ग्रहण समारोह में अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, उनकी पत्नी ऊषा वेंस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो, उनकी पत्नी जीनेट रूबियो और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी समेत कई देशों के राजनेता व धार्मिक लोग शामिल होंगे ।

लंदन में सिख दम्पति पर पाकिस्तानी गुंडों ने किया हमला

लंदन। यहां एक सिख दम्पति ने आरोप लगाया है कि उनके परिवार पर पाकिस्तानी गुंडों के एक समूह ने हमला किया तथा इसके बाद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने आरोप लगाया कि यह सब शहर के मेयर सादिक खान के आदेश के कारण हुआ। अपनी बात को साबित करने के लिए लंदन के एक रेस्टोरेंट मालिक हरमन सिंह कपूर ने कहा कि दो दिन पहले एक पाकिस्तानी को पाकिस्तानी कहने पर शहर की पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। उन्होंने दावा किया कि पुलिस ने उन पर नस्लीय भेदभाव का आरोप लगाया। कपूर ने ट्वीट किया कि कल रात मैंने पाकिस्तानियों के एक समूह द्वारा हमला किए जाने के बाद 999 पर कॉल किया। जब पुलिस आई, तो एक अधिकारी मेरी ओर दौड़ा, जबकि अन्य चिल्ला रहे थे, इसे गिरफ्तार करो! मेरा अपराध मैंने एक पाकिस्तानी कोज एक पाकिस्तानी कहा। उन्होंने मुझ पर नस्लीय रूप से उत्तेजित होने का आरोप लगाया- असली हमलावरों पर नहीं। यह सादिक खान के अधीन पुलिसिंग है। लंदन में पाकिस्तानियों के एक समूह द्वारा किए गए हमलों की अपनी व्यथा का ब्यौरा देते हुए दम्पति ने कहा कि यह पिछले ढाई वर्षों से हो रहा है, जिसके कारण अंततः पति को गिरफ्तार कर लिया गया। दंपत्ति ने एक वीडियो में कहा कि 'हमारे परिसर में ही कुछ पाकिस्तानी गुंडों ने हम पर हमला किया। हमें कुछ चोटें आई हैं। पति ने खुद को और अपने परिवार को बचाने की कोशिश की। जबकि पत्नी ने पुलिस को बुलाया। बाद में पति को गिरफ्तार कर लिया गया। क्योंकि मेरा नाम खान नहीं है और हम आतंकवादी नहीं हैं।' एक अलग वीडियो में महिला ने कहा कि पुलिस के पास हुए हमलों के सबूत हैं। मगर उन्होंने अपराधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू नहीं की है, क्योंकि वे लंदन के मेयर सादिक खान के नियंत्रण में हैं, जिनकी जड़ें पाकिस्तान में हैं।

यूएन ने चेताया कहा- गाजा, सूडान और हैती जैसा हो जाएगा पाकिस्तान का हाल

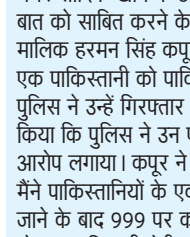

रोम। पाकिस्तान की हालत भी खराब होती जा रही है और अगर उसने अपनी स्थिति में सुधार नहीं किया, तो आने वाले दिनों में उसकी हालत गाजा और सूडान की तरह हो जाएगी। यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की कुल आबादी करीब 24 करोड़ है, जिसमें पांच से कम उम्र के 40 प्रतिशत बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। इतना ही नहीं, कुल जनसंख्या के 20 ।7 फीसद लोग ऐसे हैं, जिन्हें जीवन के जरूरी पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता ।संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इन आंकड़ों को दुनिया के लिए बेहद खतरनाक बताया। उन्होंने कहा कि दुनिया में भूख और कुपोषण के फैलने की दर हमारी नियंत्रण क्षमता से कहीं अधिक है। हालांकि वैश्विक स्तर पर उत्पादित अन्न का एक-तिहाई बर्बाद हो जाता है। एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि मानवीय जरूरतों को पूरा करने के लिए फंड में कमी होना लगातार भूखमरी जैसी वैश्विक समस्या को और जटिल बना रहा है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार, 2024 में खाद्य असुरक्षा और कुपोषण की स्थिति और खराब हुई, जिससे 53 देशों में 29.5 करोड़ लोग भूख से प्रभावित रहे।

अरब लीग शिखर सम्मेलन

फिलीस्तीन और मिस्र के राष्ट्रपतियों ने गाजा पर हमले को तुरंत रोकने की अपील की

बगदाद

इराक की राजधानी बगदाद में आयोजित 34वें अरब लीग शिखर सम्मेलन के दौरान फिलीस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास और मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल-फत्ताह अल-सीसी ने गाजा पट्टी में इस्राइली सैन्य अभियान को तत्काल और स्थायी रूप से समाप्त करने की पुरजोर अपील की।

राष्ट्रपति अब्बास ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए अरब देशों से आग्रह किया कि वे एक सामूहिक अरब योजना को अपनाएं, जिसका उद्देश्य इजराइली हमलों को रोकना और क्षेत्र में स्थायी शांति स्थापित करना हो। उन्होंने कहा कि, टिकाऊ शांति केवल इजराइली कब्जे की समाप्ति और फिलीस्तीनी जनता को उनके पूर्ण अधिकार मिलने के बाद ही संभव है। वहीं मिस्र के राष्ट्रपति अल-सीसी ने गाजा में बीते 19 महीनों से जारी व्यवस्थित अत्याचार और अमानवीय हिंसा की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि यह हिंसा फिलीस्तीनी जनसंख्या को मिटाने का प्रयास है। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय, विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका, से गाजा में मानवाधिकार संकट को समाप्त करने के लिए कड़े और प्रभावी कदम उठाने की अपील की। राष्ट्रपति अल-सीसी ने यह भी कहा कि जैसे ही संघर्ष विराम होता है, मिस्र गाजा की पुनर्निर्माण और पुनर्बहाली के लिए एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने के लिए प्रतिबद्ध है। गाजा स्थित हमास के मीडिया कार्यालय ने सम्मेलन के प्रतिभागियों से अपील की कि वे केवल बयानबाजी तक सीमित न रहें, बल्कि व्यावहारिक और साहसिक कदम उठाएं, ताकि गाजा पर थोपे गए अन्यायपूर्ण नाकाबंदी को समाप्त किया जा सके और लोगों की मानवाधिकारों की रक्षा की जा सके। हमास ने इजराइल पर दबाव बनाने और सीमा पारियों को तत्काल व बिना शर्त खोलने की मांग की ताकि खाद्य सामग्री, मानवीय सहायता और चिकित्सीय संसाधन गाजा की पीड़ित जनता तक पहुंच सकें, जो इस समय भुखमरी और जीवन संकट से जूझ रही है। सम्मेलन में लेबनान के प्रधानमंत्री नवाफ सलाम ने भी इजराइली आक्रामकता की आलोचना की और कहा कि नवंबर 2024 में हुई समझ के बावजूद इजराइल द्वारा लेबनानी क्षेत्रों पर हमले जारी हैं। उन्होंने सदस्य देशों से अपील की कि वे अंतरराष्ट्रीय समुदाय पर दबाव डालें ताकि इस्राइल अपने आक्रामक अभियान बंद करे और लेबनान से पूरी तरह पीछे हटे।

उल्लेखनीय है कि यह सम्मेलन इराक द्वारा 2003 के अमेरिकी आक्रमण के बाद आयोजित किया गया सिर्फ दूसरा शिखर सम्मेलन है। इससे पहले 2012 में ऐसा आयोजन हुआ था। इस बार सम्मेलन में 22 अरब लीग सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों और शीर्ष राजनयिकों के अलावा क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया।

नेपालः स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को समन

काठमांडू

नेपाल की एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से कथित जमीन घोटाले में स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को समन भेजा गया है। नेपाल सरकार द्वारा आयुर्वेद विश्वविद्यालय तथा शोध संस्थान बनाने के लिए पतंजलि ट्रस्ट नेपाल को सरकारी जमीन दी गई थी। इस जमीन की खरीद-बिक्री से संबंधित गड़बड़ियों की जांच चल रही है। इस मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल से भी पूछताछ की जा चुकी है। नेपाल के कंपनी रजिस्ट्रार के दफ्तर में पतंजलि योगपीठ नेपाल और पतंजलि ट्रस्ट नेपाल दोनों ही कंपनियों को गैर नाफामुलक कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड किया गया है। इन दोनों ही कंपनियों में स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण संचालक समिति में हैं जबकि नेपाल की तरफ से शालीग्राम सिंह संचालक समिति में हैं। ब्यूरो के तरफ से प्रवक्ता राजेन्द्र पौडेल ने बताया कि संचालक समिति में होने के कारण रामदेव और बालकृष्ण को समन भेजा गया था लेकिन उनकी तरफ से जून के आखिरी सप्ताह में यह जवाब आया कि नेपाल में हुई सभी खरीद-बिक्री के लिए स्थानीय प्रतिनिधि शालिग्राम सिंह जवाबदेह हैं इसलिए कानूनी रूप से उनसे ही पूछताछ की जाए। नेपाल सरकार ने कैबिनेट की मंजूरी के साथ पतंजलि योगपीठ नेपाल और पतंजलि ट्रस्ट नेपाल कॉन्जमिन हदबंदी की छूट देते हुए जमीन का आवंटन किया था। आयुर्वेद विश्वविद्यालय, आयुर्वेद शोध संस्थान, योग महाविद्यालय तथा अन्य प्रयोजन के लिए बनेपा जिले में में 61 बीघा, दांग जिले मे 75 बीघा, 22 बीघा, स्यांगजा जिले में 18 बीघा, चितवन में 15 बीघा, जनकपुर में 25 बीघा, बारा और परसा जिले में 50 बीघा और काठमांडू में 11 बीघा जमीन पतंजलि योगपीठ और पतंजलि ट्रस्ट ने अपने नाम पर खरीदा। इसके दो वर्ष के बाद ही पतंजलि ट्रस्ट नेपाल ने बनेपा में सहूलियत में मिले 61 बीघा जमीन को महंगे दाम पर बेच कर कहीं और जमीन की खरीद की। तत्कालीन नेपाल सरकार ने इस खरीद-बिक्री को अनुमति प्रदान कर दी थी लेकिन नेपाल के जमीन खरीद बिक्री कानून के मुताबिक सरकार द्वारा आवंटित जमीन की बिक्री नहीं हो सकती है।

मैक्सिकन नौसेना का जहाज ब्रिज से टकराया, दो की मौत, 19 घायल

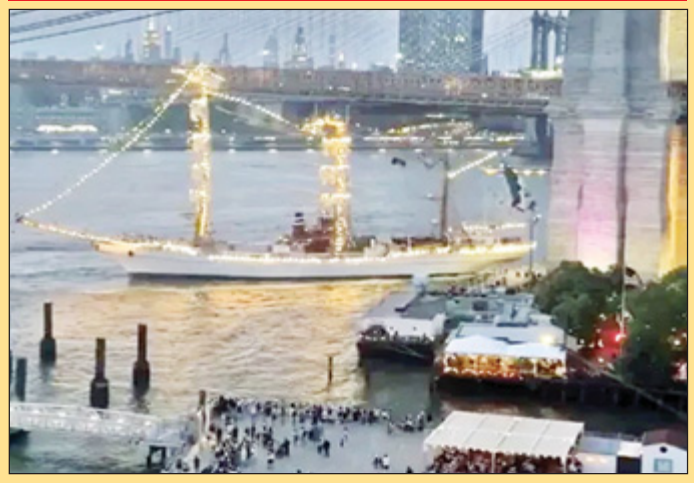

अमेरिका के न्यूयार्क में बड़ा हादसा हो गया। मेक्सिन नौ सेना का ट्रेनिंग जहाज ब्रुकलिन ब्रिज से टकरा गया। न्यूयार्क सटी के मेयर एरिक एडम्स ने बताया कि हादसे में दो लोगों को मौत होने और 19 लोगों घायल होने की खबर है ।घायलों में दो की हालत गंभीर बनी हई है। न्यूयार्क फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक हादसा शनिवार की देर शाम को हुआ। हादसे के तुरंत बाद ही रेस्क्यू आरपेरशन शुरू कर दिया गया। सभी घायलों को तुरंत ही अस्पताल में दाखिल कराया गया। हादसे के पीछे कारण क्या रहे, इसके बारे में अभी जांच की जा रही है। यह नौसेना का जहाज नौसैनिक कैडेटों को ट्रेनिंग देने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें कुल 277 लोग सवार थे, जिनमें नाविक, अधिकारी और कैडेट भी शामिल थे।

कोलंबिया ने चीन-नीत ब्रिक्स बैंक में शामिल होने के लिए आवेदन किया

शंघाई/बोगोटा

कोलंबिया ने चीन के नेतृत्व में संचालित न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) में सदस्यता के लिए आवेदन किया है। यह कदम लैटिन अमेरिकी देशों की बदलती विदेश नीति की दिशा की ओर संकेत करता है, जिसमें वे अब पारंपरिक अमेरिकी प्रभाव से हटकर चीन जैसे उभरते वैश्विक शक्ति केंद्रों की ओर रुख कर रहे हैं।

कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने हाल ही में अपने चीन दौरे के दौरान शंघाई में ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति और एनडीबी की प्रमुख दिल्मा रूसेफ से मुलाकात की। पेट्रो ने घोषणा की कि उनका देश इस बहुपक्षीय विकास बैंक में 512 मिलियन अमेरिकी डॉलर के शेयर खरीदेगा।

राष्ट्रपति पेट्रो ने विशेष रूप से उस 120 किलोमीटर लंबे नहर या रेलवे परियोजना का ज़िक्र किया जो कोलंबिया के अटलांटिक और प्रशांत महासागर के तटों को जोड़ने के लिए प्रस्तावित है। उन्होंने इसे दक्षिण अमेरिका और एशिया के बीच व्यापार के लिहाज से रणनीतिक कड़ी बताया और आशा जताई कि एनडीबी से इस परियोजना को वित्तीय सहयोग मिलेगा।

कोलंबिया एनडीबी में सदस्यता के लिए आवेदन करने वाला लैटिन अमेरिका का दूसरा देश

है। इससे पहले 2021 में उरुग्वे ने इस बैंक में शामिल होने की इच्छा जताई थी। हालांकि, कोलंबिया का यह कदम वॉशिंगटन में चिंता का कारण बन सकता है, क्योंकि यह देश अब तक अमेरिका का प्रमुख सहयोगी और वॉर ऑन ड्रग्स अभियान का समर्थनकर्ता रहा है। इस बीच, अमेरिकी विदेश विभाग ने स्पष्ट किया है कि वह लैटिन अमेरिका में चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) से जुड़ी परियोजनाओं के लिए किसी भी तरह की फंडिंग का विरोध करेगा। उल्लेखनीय है कि एनडीबी की स्थापना 10 वर्ष पहले ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका (ब्रिक्स देशों) ने मिलकर एक विकल्प के रूप में की थी ताकि विश्व बैंक और इंटर-अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक जैसे अमेरिका-प्रभुत्व वाले संस्थानों का मुकाबला किया जा सके।

चीन की विमान कंपनियों ने नेपाल का कानून मानने से क्या इनकार, सरकार को नहीं देतीं टैक्स

काठमांडू

चीन की विमान कंपनियां नेपाल के नियम कानून को नहीं मानती हैं। नेपाल आने वाले सभी विमानों की कंपनियां यहां की सरकार को टैक्स देती हैं, लेकिन चीन की कोई भी एयरलाइंस नेपाल सरकार को टैक्स नहीं देती हैं। नेपाल के ऑडिटर जनरल ने बीते दिनों अपनी वार्षिक रिपोर्ट सार्वजनिक की है।

इसमें नेपाल में उड़ान भरने वाले चार चीनी एयरलाइंस कंपनियों के द्वारा सरकार के तरफ से निर्धारित टैक्स को नहीं देने पर सवाल खड़े किए हैं। सरकार को सौंपी गई इस रिपोर्ट के

मुताबिक एयर चाइना, साउदर्न चाइना एयरलाइंस, चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस और सिचुवान एयरलाइंस ने नेपाल सरकार के द्वारा निर्धारित टैक्स नहीं दिया है।

ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में इस बात का भी उल्लेख है कि इन चारों चीनी एयरलाइंस कंपनियों से अन्य विदेशी एयरलाइंस की तरह टैक्स वसूला जाए। इसके मुताबिक दिसंबर 2024 तक इन चार चीनी एयरलाइंस कंपनी ने नेपाल सरकार को टैक्स नहीं देने से करीब 400 करोड़ रूपये का घाटा हुआ है। उन्होंने नेपाल सरकार को जल्द से जल्द टैक्स लेने अन्यथा इन विमान कंपनियों की सेवा सुविधा को बंद करने को कहा है।

वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव रहे दिनेश घिमिरे ने शनिवार को कहा कि मंत्रालय के तरफ से बार बार चारों चीनी एयरलाइंस कंपनियों को टैक्स देने को लेकर पत्राचार किया गया, लेकिन उनके तरफ से कोई जवाब नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि शुरुआत में तो चीनी राजदूत ने मंत्रालय में आकर टैक्स नहीं देने की बात की थी। चीनी राजदूत का कहना था कि चीन सरकार का नियम है विश्व में कहीं भी किसी भी एयरपोर्ट पर लैंड करने और उड़ान करने के लिए अतिरिक्त टैक्स या वैल्यू एडेड टैक्स नहीं देना पड़ता है। फिर नेपाल में क्यों दिया जाए।

राजस्व सचिव ने बताया कि जब दुनिया की सारी एयरलाइंस कंपनिया नेपाल के नियम कानून का सम्मान करते हुए यह टैक्स देती हैं तो चीन की एयरलाइंस कंपनी को भी देना चाहिए। वित्त मंत्रालय की तरफ से नागरिक उड्डयन मंत्रालय को इनकी सेवा सुविधा को बंद कर लाइसेंस रद्द करने की भी सिफारिश की गई है, लेकिन राजनीतिक कमजोरी के कारण उस पर अमल नहीं किया जा रहा है।